प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
30.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800 बजे

एच.आर.टी.सी.

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की अधिकांश मांगें मानने के बाद चालक व परिचालक यूनियन ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई बैठक के बाद यूनियन ने ये फैसला लिया। चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उपमुख्यमंत्री ने 2 सौ 5 चालकों को वरिष्ठ चालक का पद नाम, 6 महीने का चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, नई वर्दी के पैसे और सभी वित्तीय देनदारियां दो से तीन महीने के भीतर प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अब चालक व परिचालक पहले की तरह ही अपनी सेवाएं देंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आ"वस्त कराया है कि आपको सैलरी पहली तारीख को मिलेगी। माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय जी जो बोलते हैं वो करते हैं, ये दो महीने का ओवर टाइम नाइट मिलेगा हमें ये जो स्टार्टिंग से देंगे, उसके बाद जो 150 करोड़ रूपये निगम प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। कल ही इन्होंने अपने कागज पत्र जो है वो दे दिए हैं और बात भी हो गई है 150 करोड़ जब मिलेगा तो 50000 एरीयर की किस्त जो 76 करोड़ बनता है, उसके बाद आपका मेडिकल रिवर्समेंट 8 या 10 करोड़ बनेगा, हमारी लगभग सारी मांगों को मान लिया गया है तो अब गेट मीटिंग भी आज से बंद करेंगे और एक आठ से अब आठ घंटे भी करेंगे जैसे हम पहले ड्यूटी करते थे उसी तरीके से अब ड्यूटी करेगें।

सिकंदर कुमार

केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को समझती है और इसकी पूर्ति के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा आज राज्यसभा में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत विभिन्न विभागों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है। उन्होंने सिकंदर कुमार को बताया कि सरकार ने श्रवण बाधित बच्चों के लिए

पीएम–ई–विद्या चैनल शुरू किया है जो इन बच्चों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है।

राजीव भारद्वाज

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक लगभग 24 हज़ार 9 सौ 68 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से 22 हज़ार 3 सौ 80 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा कर लिया गया है। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के एक सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि योजना के चौथे चरण के अंतर्गत मार्च 2029 तक देश में 25 हज़ार गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2027–28 तक 8 हज़ार किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।

फोरलेन कंपनी

शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने फोरलेन निर्माण कंपनी को शिमला के भट्टाकुफर में 30 जुलाई को ईमारत गिरने से हुए नुकसान की एवज़ में प्रभावितों को 5 करोड़ 61 लाख रूपए का मुआवज़ा देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर ए.डी.एम. शिमला पंकज शर्मा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रभावितों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए मुआवज़े की राशि का जल्द भुगतान किया जाए।

मौसम

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में मॉनसून की वर्षा रूक–रूक कर जारी है। भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण चंडीगढ़–मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित राज्य में 3 सौ 43 सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरूद्ध हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा ज़िलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर व हमीरपुर जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।